



{W.P.(C) No. 2986/2020}

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका सिविल क्रमांक -2986 वर्ष 2020

वसीम अली अंसारी, श्री रोजिद अली अंसारी के पुत्र, आयु लगभग 28 वर्ष, घर संख्या 2/23, अग्रसेन गली, महंतपारा, शेरोनीरायन, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़।

... याचिकाकर्ता

विरुद्ध

1.राज्य छत्तीसगढ़, सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, श्रम, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, जिला रायपुर 492002, छत्तीसगढ़।

2.छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, इसके रजिस्ट्रार के माध्यम से, उत्तर पार्क एवेन्यू, सेक्टर 8, भिलाई, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ 490009।

3.राज्य छत्तीसगढ़, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर, पी.एस. राखी, पी.ओ. मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492002।

4.अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, इसके अध्यक्ष के माध्यम से, 7 वीं मंजिल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई दिल्ली 110001।

5.राज्य छत्तीसगढ़, प्रमुख सचिव, विधि और विधायी कार्य विभाग, महानदी भवन, राजधानी परिसर, मंत्रालय, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

... प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए:श्री आकाश के. कुडू, अधिवक्ता।

प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 5 / राज्य के लिए: श्री अरविंद दुबे, सरकारी वकील।

प्रतिवादी संख्या 2 / सीएसवीटीयू के लिए: कोई उपस्थित नहीं, हालांकि समन भेजा गया और प्रत्युत्तर दायर किया गया।

प्रतिवादी संख्या 4/एआईसीटीई के लिए:कोई उपस्थित नहीं, हालांकि समन भेजा गया और प्रत्युत्तर दायर किया गया।

खण्डपीठ:-

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल ,न्यायाधीश एवं
माननीय श्री राधाकिशन अग्रवाल,न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश



(14/11/2024)

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश,

1. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय की असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग करते हुए, याचिकाकर्ता, जो एक इंजीनियरिंग स्नातक है (बीई (सिविल)), ने यह रिट याचिका दायर की है, जिसमें छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय – प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा 3-10-2019 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जो 2004 के छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम (संक्षेप में, 'अधिनियम 2004') की धारा 39(2) के तहत जारी किए गए बी.ई. 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के अध्यादेश के धारा 9.8.1 में संशोधन करती है, और इसे असंवैधानिक और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16

और 21 के तहत उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी गई है।

2. उक्त चुनौती निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में दी गई है:-

3. यहां याचिकाकर्ता ने 2014-2015 में प्रतिवादी संख्या 2 विश्वविद्यालय से बीई (सिविल) द्वितीय श्रेणी में 64.60% अंक प्राप्त किए और उस समय के अनुसार अध्यादेश के अनुसार उन्हें द्वितीय श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया। 2004 के अधिनियम की धारा 39(2) के तहत बी.ई. 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अध्यादेश में संशोधन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति ने 3-10-2019 की विवादित अधिसूचना द्वारा धारा 9.8.1 में संशोधन किया, जिसके तहत जो छात्र बी.ई., बी.आर्क और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें प्रथम श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया जाएगा और यह संशोधन 27-8-2018 से प्रभावी हुआ। यह प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को एक नया डिग्री प्रमाणपत्र जारी किया जाए, जिसमें यह कहा जाए कि उसने बीई (सिविल) प्रथम श्रेणी में पास किया है। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि 3-10-2019 की अधिसूचना, जिसे 27-8-2018 से प्रभावी किया गया है, को इस हद तक रद्द किया जाए कि वह जिस तिथि से प्रभावी हुई है, यानी 27-8-2018, और प्रतिवादी



{W.P.(C) No. 2986/2020}

संख्या 2 विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाए कि उक्त अधिसूचना को 2004 के अधिनियम की धारा 39(2) के तहत कार्यकारी परिषद द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने की तिथि से प्रत्यावर्ती प्रभाव दे। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (वेतनमान, सेवा शर्तें और तकनीकी संस्थानों (डिग्री) में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के लिए योग्यताएँ) विनियम, 2010 (संक्षेप में, '2010 के विनियम') बनाए हैं और विश्वविद्यालय पर यह अनिवार्य था कि वह AICTE द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुरूप या उनके अनुसार अध्यादेश promulgate करे और अन्यथा, यदि दोनों में कोई संघर्ष हो, तो केंद्रीय कानून ही लागू होगा।

4. राज्य और विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्युत्तर दायर किया गया है, जिसमें रिट याचिका में की गई दलीलों का विरोध किया गया है, यह कहते हुए कि कार्यकारी परिषद द्वारा अध्यादेश संख्या 14 (बी.ई. 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए अध्यादेश) में संशोधन करते हुए धारा 9.8.1 में किए गए संशोधन, जिसे कुलपति महामहिम द्वारा अनुमोदित किया गया, कानून के अनुसार है और रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

5. श्री आकाश के. कुंडू, याचिकाकर्ता के लिए उपस्थित वरिष्ठ वकील, यह प्रस्तुत करेंगे कि विश्वविद्यालय संशोधन को प्रत्यावर्ती प्रभाव न देने में पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है, क्योंकि यह याचिकाकर्ता के प्रथम श्रेणी में श्रेणीबद्ध होने के अधिकार को प्रभावित करेगा, और इसलिए इसे 2010 के नियमों के लागू होने के समय प्रत्यावर्ती प्रभाव देने का निर्देश दिया जाना चाहिए। वे अपनी प्रस्तुतियों को समर्थन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर निर्भर होंगे, जैसे कि रुंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज, भिलाई और अन्य बनाम छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय और अन्य¹ और राज्य बनाम तमिलनाडु और अन्य बनाम अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट और अन्य²।

1 (2015) 11 SCC 291

2 (1995) 4 SCC 104



6. श्री अरविंद दुबे, वरिष्ठ सरकारी वकील जो राज्य / प्रतिवादी संख्या 1, 3 और 5 के लिए प्रस्तुत हुए हैं, यह प्रस्तुत करेंगे कि विश्वविद्यालय ने सही तरीके से अध्यादेश संख्या 14 में संशोधन किया है, जिसे कार्यकारी परिषद ने 2004 के अधिनियम के तहत अपनी वैधानिक शक्ति में जारी किया है, इस प्रकार, रिट याचिका को खारिज किया जाना चाहिए।

7. प्रतिवादी संख्या 2 विश्वविद्यालय के लिए कोई उपस्थित नहीं हुआ है, हालांकि प्रत्युत्तर दायर किया गया है। इसी तरह, प्रतिवादी संख्या 4 एआईसीटीई के लिए भी कोई उपस्थित नहीं हुआ है।

8. हमने पक्षों के वरिष्ठ वकीलों की दलीलें सुनीं और ऊपर दी गई उनकी विरोधी प्रस्तुतियों पर विचार किया और साथ ही रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री को अत्यधिक सावधानी से देखा।

9. प्रतिवादी संख्या 2 विश्वविद्यालय 2004 के अधिनियम के तहत गठित किया गया है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति विश्वविद्यालय को 2004 के अधिनियम की धारा 38 के तहत दी गई है और अध्यादेश बनाने की प्रक्रिया धारा 39 में प्रदान की गई है, जो इस प्रकार है:

“39. अध्यादेश कैसे बनाया जाएगा.-(1) पहले अध्यादेश को छोड़कर सभी अध्यादेश कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए जाएंगे।

(2) कार्यकारी परिषद द्वारा बनाया गया अध्यादेश कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित होने की तारीख से लागू होगा।”

10. उक्त प्रावधान का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह स्पष्ट होता है कि पहला अध्यादेश छोड़कर सभी अध्यादेश कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए जाएंगे और कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए गए अध्यादेश को कुलपति द्वारा अनुमोदित किए जाने की तिथि से लागू किया जाएगा। यहां तक कि कार्यकारी परिषद को प्रत्यावर्ती प्रभाव से अध्यादेश बनाने की कोई शक्ति नहीं दी गई है, क्योंकि यह कुलपति द्वारा अनुमोदित किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा।



{W.P.(C) No. 2986/2020}

11. 2004 के अधिनियम की धारा 22 में कार्यकारी परिषद का प्रावधान है और कार्यकारी परिषद विश्वविद्यालय का कार्यकारी निकाय होगी और इसमें कुलपति अध्यक्ष के रूप में होंगे, इसके अलावा सोलह अन्य सदस्य होंगे, कुल मिलाकर 17 सदस्य होंगे। कार्यकारी परिषद की शक्तियाँ और कर्तव्य 2004 के अधिनियम की धारा 23 में प्रदान की गई हैं। इस प्रकार, कार्यकारी परिषद 2004 के अधिनियम के तहत गठित एक कानूनी निकाय है जो विश्वविद्यालय के सभी महत्वपूर्ण मामलों के लिए जिम्मेदार है।

12. अधिनियम संख्या 14 कार्यकारी परिषद द्वारा 4 वर्षीय बीई डिग्री पाठ्यक्रम के लिए जारी किया गया है, जो पहले से लागू है। उक्त अधिनियम के क्लॉज 9.8 में वर्ग या श्रेणी पुरस्कार का प्रावधान है और क्लॉज 9.8.1 यह बताता है कि किसे उत्कृष्टता या सम्मान, **श्रेणी I** और **श्रेणी II** प्राप्त करने पर श्रेणीबद्ध किया जाएगा। यह निम्नलिखित के रूप में कहा गया है:

9.8. कक्षा या श्रेणी का अधिनिर्णय

9.8.1 बी.ई./बी.टेक. डिग्री वाले छात्र को दी जाने वाली कक्षा/श्रेणी का निर्धारण छात्र के अंकों के प्रतिशत के आधार पर किया जाता है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है

•विशिष्टता या सम्मान: $75\% \leq \text{अंक} \leq 100\%$

•कक्षा I: $65\% \leq \text{अंक} < 75\%$

•कक्षा II: $50\% \leq \text{अंक} < 65\%$

इस असंशोधित अध्यादेश में, 65% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

13. अब, विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने अध्यादेश संख्या 14 के क्लॉज 9.8.1 में संशोधन किया है और 27-8-2018 को कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसके



तहत जो छात्र 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करेंगे, उन्हें 27-8-2018 से प्रथम श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया जाएगा और इसे संबंधित अधिसूचना द्वारा सूचित किया गया है उक्त अधिसूचना को इस रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी जा रही है, इस आधार पर कि अधिसूचना को 2010 के नियमों के लागू होने की तिथि, अर्थात् 22-1-2010 से प्रत्यावर्ती प्रभाव दिया जाना चाहिए था।

14. संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं के पास उन क्षेत्रों में विधायन की पूर्ण शक्तियाँ होती हैं जो उन्हें सौंपे गए हैं, और कुछ संविधानिक और न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त प्रतिबंधों के अधीन, वे भविष्यवर्ती और प्रत्यावर्ती दोनों प्रकार से विधायन कर सकती हैं। प्रत्यावर्ती विधान बनाने की शक्ति विधानमंडल को एक संशोधन अधिनियम को पूरी तरह से समाप्त करने और कानून को संशोधन अधिनियम से पहले जैसी स्थिति में बहाल करने की अनुमति देती है। यह निर्माण का एक मूल सिद्धांत है कि प्रत्येक अधिनियम प्राथमिक रूप से भविष्यदृष्टि (prospective) होता है, जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक रूप से प्रत्यावर्ती प्रभाव देने के लिए नहीं बनाया गया हो। जब तक कि अधिनियम में ऐसे शब्द न हों जो विधानमंडल की मंशा को दिखाते हुए मौजूदा अधिकारों पर प्रभाव डालने का संकेत दें, इसे "केवल भविष्यदृष्टि (prospective) माना जाता है - "नोवा कॉन्स्टिट्यूटियो फ्यूचुरिस फॉर्मम इंपोनेरे डिबेट नॉन प्रेतेरिटिस" - नया कानून वही नियमन करेगा जो आगे आने वाला है, न कि अतीत को। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अधिनियम को प्रत्यावर्ती बनाने के लिए एक स्पष्ट प्रावधान किया जाए और प्रत्यावर्ती प्रभाव के खिलाफ सामान्य धारा को आवश्यक निहितार्थ द्वारा खंडित किया जा सकता है, विशेष रूप से ऐसे मामले में जहाँ नया कानून एक स्वीकृत दोष को समुदाय के भले के लिए सुधारने के लिए बनाया गया हो। (देखें "वैधानिक व्याख्या के सिद्धांत" न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा, 15 वीं संस्करण, पृष्ठ 408-410)।



{W.P.(C) No. 2986/2020}

15. यह स्पष्ट रूप से स्थापित कानून है कि अधीनस्थ विधान को प्रत्यावर्ती प्रभाव दिया जा सकता है यदि इस संबंध में शक्ति मुख्य अधिनियम में दी गई हो।

16. महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स (P) लिमिटेड बनाम हरियाणा³ राज्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट के उनके श्रीमानों ने निम्नलिखित निर्णय दिया: (SCC पृष्ठ 633, पैरा 41-43)।

"41. हम इस चरण में उक्त नोट के छूट जाने के प्रभाव पर विचार कर सकते हैं। यह किसी भी संदेह से परे है कि अधीनस्थ कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव और पूर्वव्यापी संचालन दिया जा सकता है, यदि इस संबंध में कोई शक्ति मुख्य अधिनियम में निहित है। नियम बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित कानून की एक प्रजाति है। इसलिए एक प्रत्यायोजित व्यक्ति केवल इसके चारों कोनों के भीतर ही नियम बना सकता है।

42. यह कानून का एक मौलिक नियम है कि किसी भी कानून को पूर्वव्यापी प्रभाव वाला नहीं माना जाएगा जब तक कि ऐसा निर्माण अधिनियम की शर्तों में बहुत स्पष्ट रूप से प्रकट न हो, या आवश्यक और अलग निहितार्थ से उत्पन्न न हो। (देखें वेस्ट बनाम ग्वेने⁴)

43. प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से किए गए संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव अधिनियम की धारा 64 की उपधारा (2-ए) के लागू होने के बाद ही दिया जा सकता है, न कि उससे पहले।" एमआरएफ लिमिटेड बनाम सहायक आयुक्त (मूल्यांकन) बिक्री कर⁵।"

17. महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स (P) लिमिटेड (उपर्युक्त) में स्थापित कानून का सिद्धांत MRF लिमिटेड (उपर्युक्त) में अपनाया गया है और उसके बाद राज्य राजस्थान और अन्य बनाम बसंत एग्रोटेक (इंडिया) लिमिटेड⁶ में भी।

18. भारतीय खनिज उद्योग संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में⁷, सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों ने उपविधि और प्राधिकृत विधियों की पूर्व प्रभावी लागू होने की दृष्टि पर विचार किया और यह निर्णय दिया कि जब तक मुख्य अधिनियम स्पष्ट रूप से या

3 (2006) 3 SCC 620

4 (1911) 2 Ch 1; 104 LT 759 (CA)

5 (2006) 8 SCC 702

6 (2013) 15 SCC 1

7 (2017) 16 SCC 186



{W.P.(C) No. 2986/2020}

आवश्यक रूप से उपविधि को पूर्व प्रभाव से नियम बनाने का अधिकार नहीं देता, तब तक उपविधि को पूर्व प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं किया जा सकता माननीय न्यायाधीशों द्वारा इस पर निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की गई है:

“26. अधीनस्थ विधायिका को पूर्वव्यापी प्रभाव देने की शक्ति, चाहे वह नियमों या विनियमों या अधिसूचनाओं के रूप में हो, इस न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में चर्चा का विषय रही है और उन सभी पर विचार करना आवश्यक नहीं है – वास्तव में ऐसा करना संभव भी नहीं हो सकता है। यह पर्याप्त होगा यदि हमारे सामने उद्धृत इन निर्णयों में से कुछ द्वारा निर्धारित सिद्धांत और हमारी चर्चा के लिए प्रासंगिक सिद्धांतों को अलग कर दिया जाए। ये स्पष्ट रूप से मामलों के वर्तमान सेट से संबंधित हैं और इनका उद्देश्य विधियों या अधीनस्थ विधानों के पूर्वव्यापी संचालन के सभी मामलों के लिए कानून बनाना नहीं है। सुसंगत सिद्धांत हैं:

(i) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार (या कोई अन्य प्राधिकारी) पूर्वव्यापी प्रभाव वाला कोई अधीनस्थ कानून नहीं बना सकती, जब तक कि मूल कानून स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत न करे। [हुकम चंद बनाम भारत संघ⁸ और महाबीर वेजिटेबल ऑयल्स (पी) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य³]

(ii) प्रत्यायोजित विधान सामान्यतः भावी प्रकृति का होता है और पहली बार अधिकार या दायित्व पूर्वसंबंध प्रभाव नहीं दिया जा सकता है। (पंची देवी बनाम राजस्थान राज्य⁹)

(iii) राजकोषीय कानून से संबंधित अधीनस्थ विधान के संबंध में, यह मानना उचित नहीं होगा कि किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में कोई प्रत्यायोजित प्राधिकारी कर या शुल्क लगा सकता है। किसी नागरिक से जबरन वसूली के संबंध में इरादे की कोई गुंजाइश या कोई गुंजाइश नहीं है।

[अहमदाबाद शहरी विकास। प्राधिकरण बनाम शरदकुमार जयंतीकुमार पासावाला¹⁰ और राजस्थान राज्य बनाम बसंत एगोटेक (इंडिया) लिमिटेड⁶]

27. इस विषय पर बहुत अधिक विद्वत्तापूर्ण, सामान्य और व्यापक चर्चा सीआईटी बनाम वाटिका टाउनशिप (पी) लिमिटेड¹¹ में संविधान पीठ के निर्णय में पाई जा सकती है और हम स्पष्ट रूप से उसमें प्राप्त निष्कर्षों से बंधे हुए हैं। हमारे लिए संविधान पीठ द्वारा की गई चर्चा और निष्कर्षों को दोहराना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है, वह यह है कि हमारे निष्कर्ष संविधान पीठ द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से अलग नहीं हैं

⁸ (1972) 2 SCC 601

⁹ (2009) 2 SCC 589; (2009) 1 SCC(L&S) 408

¹⁰ (1992) 3 SCC 285

¹¹ (2015) 1 SCC 1



19. इस प्रकार, यह अब पूरी तरह से स्थापित है कि हर कानून को प्राथमिक रूप से भविष्य में लागू होने वाला माना जाएगा, जब तक कि उसे स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ के माध्यम से पूर्व प्रभावी होने का प्रावधान न किया गया हो। यह भी सिद्ध कानून है कि जो शक्ति उपविधि बनाने के लिए दी जाती है, उसे हमेशा मुख्य अधिनियम के अनुरूप ही प्रयोग किया जाना चाहिए। उपविधि को पूर्व प्रभाव और संचालन दिया जा सकता है, यदि मुख्य अधिनियम में इस संबंध में कोई शक्ति दी गई हो, जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा उपरोक्त निर्णयों में कहा गया है।

20. वर्तमान मामले के तथ्यों पर पुनः विचार करते हुए, आपत्ति की गई संशोधन आदेश संख्या 14 विश्वविद्यालय के कार्यकारी परिषद द्वारा 2004 के अधिनियम की धारा 39(1) के तहत प्रदान की गई शक्ति का उपयोग करते हुए किया गया है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 2004 के अधिनियम की धारा 39(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कार्यकारी परिषद द्वारा बनाए गए आदेश को उस दिन से लागू माना जाएगा जब उसे कुलपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है और वर्तमान मामले में, कुलपति द्वारा अनुमोदन 27-8-2018 को दिया गया था, हालांकि, 2004 के अधिनियम की धारा 39(2) या उक्त अधिनियम की किसी अन्य प्रविधान के तहत कार्यकारी परिषद / आदेश बनाने वाली प्राधिकरण को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह कुलपति द्वारा अनुमोदित तिथि से पूर्व के प्रभाव से आदेश जारी कर सके और आदेश संख्या 14 (बीई 4 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के लिए आदेश) की धारा 9.8.1 में संशोधन कार्यकारी परिषद द्वारा 2004 के अधिनियम की धारा 39(2) के पूर्ण अनुपालन में किया गया है और इसे 27-8-2018 से प्रभावी किया गया है, यानी उसी तिथि से जब कुलपति ने आदेश संख्या 14 की धारा 9.8.1 में किए गए संशोधन को अनुमोदित किया, जिसके तहत बी.ई.,



बी.आर्क और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 60% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत किया जाएगा। 2004 के अधिनियम की धारा 39(2) के तहत कार्यकारी परिषद / नियम बनाने वाली प्राधिकरण को पूर्व प्रभाव से आदेश बनाने का अधिकार और क्षेत्राधिकार न होने के कारण, कार्यकारी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा अनुमोदन की तिथि से प्रभावी नियम बनाना पूरी तरह से उचित है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा जो निर्णयों पर भरोसा किया गया है, जैसे कि **रूंगटा इंजीनियरिंग कॉलेज (पूर्वोक्त) और अधियामन एजुकेशनल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट का मामला (पूर्वोक्त)**, वे तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से भिन्न हैं और वर्तमान मामले पर लागू नहीं होते।

21. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हम यह मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने 3-10-2019 की अधिसूचना को रद्द करने का उचित कारण प्रस्तुत नहीं किया है, जो विश्वविद्यालय द्वारा 2004 के अधिनियम की धारा 39(2) के तहत आदेश संख्या 14 में किए गए संशोधन को लागू करती है। इसके परिणामस्वरूप, याचिका खारिज की जाती है और पक्षकार अपने-अपने व्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही / -

संजय के. अग्रवाल

न्यायाधीश

सही / -

राधाकिशन अग्रवाल

न्यायाधीश



{W.P.(C) No. 2986/2020}

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

